में आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ;

(ख) सरकार हस्तशिल्प पर आधारित कुटीर उद्योगों और भारत और विदेशों में इनके उत्पादों की बिक्री हेतु मंडियां तलाश करने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन देगी ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने लिए कि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपयुक्त दरों पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) परम्परागत उद्योगों सहित, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार रियायती वित्त कच्चा-माल तथा प्रशिक्षण संबंधी सहायता आदि देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। हस्त-शिल्प के क्षेत्र में चालू योजनायें मिश्रित स्वरूप की हैं। और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई विशेष अभ्युपाय की परिकल्पना नहीं की गयी है। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता रूप से जोर दिया जाता है। इसी प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को अवसर उपलब्ध कराने पर बल देते हुए स्थानीय संसाधनों व स्थानीय दक्षता का इस्तेमाल करते हुए उद्योगों के विकास की ओर उन्मुख है।

(ख) और (ग) हस्तशिल्प पर आधारित उद्योगो की विपणन आवश्यकताओं के संबंध में "विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्रों" के नाम से जाने जाने वाले संगठनों की एक श्रृंखला द्वारा काफी हद तक ध्यान किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास उत्पादों का विपणन बढ़ाने के लिए देश में बहुत बड़ी संख्या में बिक्री केन्द्र हैं। विदेशी बाजारों में बाजार सम्भावना का पता करने में हस्तशिल्प उद्योगों के सहायतार्थ निम्नलिखित संवर्धनात्मक अभ्युपाय भी किये गये हैं :-

(1) विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिये बाजार विकास सहायता उपलब्ध है ;

(2) निर्यात संभावना का पता करने के लिए समय-2 पर बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित किए जाते है ;

(3) तकनीकी शिष्ट मंडल/विशेषज्ञों को उत्पाद तकनीकों के बारे में अध्ययन करनेहेतु विदेशों को भेजा जाता है ताकि विदेशी बाजारों में व्यापक रूप से स्वीकार करने के लिए उत्पाद-गुणवत्ता में सुधार किया जा सके ।

राज्य हस्तलिप विकास निगमों को कच्चे माल की नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल के डिपो स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग यथासभव अपने सहायता प्राप्त अभिकरणो को उचित दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति कराने में भी सहायता प्रदान करता है ।

Nomination of directors on the Board of Managment of the Peerless General Finance and investment company Limited

3214. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Calcutta High Court has in a recent judgement upheld the petition of the Peerless General Finance and Investment Company against a decision of the Company Law Board to nominate four Directors on the Board of Management of the Peerless under section 408 of the Companies Act, 1956; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and what steps Government would propose to take to protect the interests of the certificate holders and the public investors?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is receiving the attention of the Government.

Diesel car developed by Premier Automobiles Limited

3215. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether in early 1989 there would be entry of a diesel car on the Indian roads from Premier Automobiles Limited;

(b) if so, what will be the total cost involved in its manufacture;

(c) what will be the number of such cars to be produced at the initial stage; and

(d) to what extent it will be economical vis-a-vis petrol driven cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The company has stated that it proposes to introduce a diesel version of passenger car in 1989.

(b) The cost of the proposed car has not yet been worked out by the company.

(c) The company proposes to manufacture 3,600 cars during the first year of its commercial production.

(d) Since the cost of the diesel version of the car has not yet been worked out, such a comparison is not possible at this stage.

Chhabaria group of Industries

3216. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of INDUSTRY be peased to state:

(a) whether it is a fact that the Chhabaria Group which has recently taken over Shaw-Wallace, is trying to enter the Peerless General Finance and Investment Company; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Ministry of Industry has no information in this regard.

(b) Does not arise.

Pattern of Equity share holding in the M/s Peerless General Finance and Investment Company

3217. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what was the pattern of equity share holding in the Peerless General Finance and Investment Company, before the sale of some shares to NICCO Group of industries in 1986;

(b) what was the pattern of share holding in the company after the sale of shares by Shri Parasmall Lodha, Director of the Peerless Company to other Director of the Company, Shri S. K. Roy; and

(c) whether it is a fact that as a result of unscrupulous manipulation, Shri Roy has increased his holding considerably, which will enable him to have a dominant position in the management of the Company?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The pattern of equity